

भारतीय राजनीतिक प्रणाली में चुनावी फैसले की सीमाएं

□ डॉ॰ रजनी शोमरी

हाल ही के कुछ समय में प्रधानमंत्री ने एक वर्ष पूर्व भारी बहुमत से चुनी गई सरकार के लिए, एक बड़ती हुई चुनौती के विषय में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है।

स्वतंत्रता दिवस पर 'सूर्य' पत्रिका की दिये गये संदेश में उन्होंने कुछ विरोधी गुटों पर यह आरोप लगाया कि वे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जो जनता द्वारा किए गए प्रसक्तों को खनट दें, यू० एन० आई० की एक रिपोर्ट के अनुसार २ अगस्त की केबिनेट मंत्रियों तथा अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में श्रीमती गांधी ने पार्टी में उत्पन्न गूट स्पर्धा के खिलाफ उन्हें सजग कराया और बताया कि किस प्रकार अति भारी शासनशैल निलने पर श्री जनता पार्टी को आंतरिक झगड़ों के कारण अयोग्य बनाकर सरकार छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी का यह सोचनीय लेखा-जोखा इस संदर्भ में इन्दिरा काँग्रेस के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। १५ अगस्त को लाल किले से दिये गए अपने भाषण में उन्होंने विरोधी दलों से सगड़े का रास्ता छोड़कर अपनी सरकार से सहयोग करने का अनुरोध किया।

यह दक्षत्व जनता पार्टी के नेताओं के उन वक्तव्यों की, जब उनके सामने श्रीमती गांधी की चुनौती थी, तथा श्रीमती गांधी के स्वयं के उन वक्तव्यों की याद दिलाते हैं जब वे सोचती थीं कि अवशकाश नारायण उनकी वैधानिक ढंग से बनी सरकार के विरुद्ध जनता को उकसा रहे थे।

इस प्रकार के वक्तव्य निराशा राजनीतियों की

निरर्थक उठान-कूद नहीं है। यद्यपि तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में बिजय सत्ता में जाने रहने के लिए एक लक्ष्यपन्त वाग्वर सिद्ध होती रही है, तथा वैधानिक ढंग से गठित सरकारों को यह चुनौती केवल विरोधी बलों की ओर से ही नहीं, बल्कि जनता के उन बड़े समूहों की ओर से भी दी जा रही है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर असम्युष्ट तथा बहिष्कार हो गये हैं।

इसके कारण हैं : निम्नलिखित तथ्यावली नीति की बदली हुई खाईयों के एक दौर के बाद हुए पिछले तीन प्रभावशाली चुनावों में मतदाताओं ने निष्पक्षालनक ढंग से हस्तक्षेप। उसने पुराने सत्ताधारी गुटों को निकास फेंका, जैसे सिटीकेट को १९७१ में, श्रीमती गांधी की सरकार को १९७७ में, और जनता सरकार को १९८० में। तथा नयी सरकारों को स्पष्ट एवं ठोस बहुमत प्रदान किया। जनता द्वारा किये गए वे स्पष्ट फैसले 'गरीबी हटाओ', 'स्वतंत्रता के साथ रोटी बिनाओ' तथा 'कानून करनेवाली सरकार को सौचो' जैसे आह्वानों से प्रेरित थे। किन्तु सहीजा कुछ नाटकीय कानून एवं संवैधानिक संशोधन करने तथा कानूनी दृष्टि, मैत्री के अभाव और कुछ नहीं निकला। जामरुत मतदाताओं के लिए यह निष्कर्षना सत्ता बनकर शीर्षनिय ढंग से उनके सामने आई कि वे एक अकर्मण्य एवं अनोकरिय सरकार को हटा तो सकते हैं, किन्तु उनके पास निष्पक्षालनक ढंग से यह माजूम करने का कोई उपाय नहीं है कि जो नयी सरकार वे बना रहें हैं वह भाषातीत काम करेगी।

एक प्रभावशाली सरकार बना पाने में चुनावी फैसलों की वसतुलता के साथ-साथ चुनी हुई सरकारों को ऐसी स्थिति में एक और गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है, और यह है उनकी वैधता में घाटी अवनाति। यह जहाँ सांख्यिक रूप से उनकी अकर्मण्यता का परिणाम है वहीं उससे युक्त भी है। यह मुख्यतः एक और चुनाव भाषाविक एवं पार्टी राजनीति में बढ़ते हुए असहजवर्ष (अस-मन्ध) का, तो दूसरी ओर सरकारी प्रक्रिया का फल है। जनता के लिए अब भी पार्टी प्रमुख है। 'सरकार' उसकी नजरों में एक विशेष शक्तिशाली गुट का साकार रूप है और चुनाव पुराने समीकरणों को हटाकर नये समीकरणों को स्थापित करने का अवसर मात्र है। सत्ताधारी गुट के लिए पार्टी केवल धोड़ पाने का साधन तथा जनप्रिय अपील

करने का एक संघ है। एक बार सरकार में जम जाने के उपरान्त यह सत्ताधारी गुट पार्टी को दूसरे चुनाव आने तक भुलाये रखता है। फलस्वरूप प्रत्यक्ष बोध (ज्ञान, अन्त-राम) और सहज बुद्धि (विवेक, समझ) के बीच दूरार बनती है जो सरकार की चुनी गई अवधि के लिए की गई जनन-बद्धता में टांक लगाती है। जिसके कारण जनता को वह फैसला जिसकी ओर प्रधानमंत्री ने संकेत किया या धर्महीन बन जाता है। ऐसा १९७१ में हुआ, १९७७ में हुआ और दिखाता है १९८० में भी यही होगा।

इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी सत्य है। यह प्रणाली प्रतिभाशाली व पचनबद्ध लोगों को, जिन के पास एक आधुनिक राज्य बनाने का आवश्यक ज्ञान एवं प्रतिभा है, सत्ता की बसमा कम-से-कम उस स्थिति में को जो ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अपने ईर्ष्या-गिद्ध हकठठा कर उनसे काम ले सकें, आगे धाकर सत्ता की कुर्तियों पर बैठाने में अक्षम होती जा रही है। प्रजातांत्रिक रूप से काम करने में पार्टी का महत्व एक मुख्य प्रकरण के रूप में बढ़ता जा रहा है। विविध क्षमता एवं ज्ञान की पुष्टिसुमि वाले लोगों की पार्टी के कार्यालयों तथा नीति निर्धारण मंचों पर उपस्थिति ने इस प्रणाली को एक सर्वभार्य प्रमुख सम्पन्न विशेष विधिष्ठान संपुष्टय को मन्ध देती में अस-फल बनाया है। इसी प्रकार संघात्मक ढाँचे तथा स्थानीय प्रकरणों का कमजोर होना यह प्रकट करता है कि विभिन्न परिस्थितियों के बारे में ज्ञान की गहराई व पूरी समझ-बूझ के साथ महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते हैं।

उत्तराल रूप में जो लोग उच्चतम स्थानों के लिए चुने जा रहे हैं उन्हें निम्न स्तरों अथवा दूसरे परिष्ठानों का कोई पूर्व अनुभव नहीं होता। प्रजातांत्रिक विधि का केवल एक चुनाव खेल में परिणत हो जाने से यह प्रणाली उनके लिए घुबसे ही गई है, जिनका सत्ता के लिए एक मात्र दावा ऊँचे लोगों में सहज पहुँच, स्थानीय अथवा पारि-वारिक सम्बन्ध या धन है। ऐसे राजनीतिज्ञ पण रहें हैं जो किसी और की समोहन आक्ति पर एवं जनता की सात्त्विक चिन्ताओं से फायदा उठाकर, एक बार चुनाव जीतने के उपरान्त गुटों की जोड़तोड़ में निरंतर सट-पाट बैठकर ऊपर छठों से साहिर हैं। किन्तु उनका यही कोशल उन्हें जनता की प्रसारी की समस्यार्थ सुलसावे तथा व्यापक रूप से आबर एवं विश्वसनीयता प्राप्त कराने में

